

यूपी में बनेगा विमान ईंधन... ढाई करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा

बायो जेट फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति लाएगी सरकार, गन्ने की खोई और गेहूं के भूसे से बनेगा ईंधन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में गन्ने की खोई, धान की भूसी और गेहूं के भूसे से विमान का ईंधन बनेगा। इसके लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। उत्तर प्रदेश इससे संबंधित नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नई नीति का सीधा लाभ प्रदेश के 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने से उनकी आय में इजाफा होगा।

इन्वेस्ट यूपी ने बायो जेट फ्यूल (एसएएफ) के विनिर्माण में अवसरों की तलाश के लिए रविवार को एक उच्चस्तरीय सम्मेलन किया। इसमें उत्तर प्रदेश सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को प्रस्तुत किया गया। इस पर विचार-विमर्श के साथ ही हरित ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाएं तलाशी गईं।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्य



इन्वेस्ट यूपी की बैठक में निवेशकों से बात करते मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। -स्रोत: सूचना विभाग

किसानों को मिलेगा नया बाजार

बैठक में बताया गया कि एसएएफ उद्योगों की स्थापना के बाद राज्य के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसमें गन्ने की खोई, धान की भूसी, गेहूं का भूसा और अधिशेष अनाज की मांग किसानों के लिए नए बाजार अवसर पैदा करेगी। स्थानीय कृषि क्षेत्रों से सीधे कच्चा माल खरीदने से यह क्षेत्र ग्रामीण आय को बढ़ाने और बेहतर मूल्य दिलाने में मददगार होगा। मुख्य सचिव ने कहा, यह नीति न केवल हमारे हरित ऊर्जा क्षेत्र में तेजी लाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि हमारे किसानों को इसका लाभ मिले।



3000

करोड़ का निवेश
आने की संभावना

मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रीनको, एएम ग्रीन्स, ई20 ग्रीनफ्यूल्स, न्यू एरा क्लीन टेक और मालब्रोस ग्रुप सहित 18 से अधिक कंपनियों ने राज्य में एसएएफ इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इन फर्मों ने सामूहिक रूप से यूपी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में 3000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की बात कही है।

सचिव ने प्रस्तावित एसएएफ नीति में शामिल प्रोत्साहनों, सुविधाओं और नीतियों को रेखांकित किया। यहां की समृद्ध कृषि संपदा, सुदृढ़ बुनियादी

ढांचे और औद्योगिक नीतियों को एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने में सहायक बताया। बैठक में भूमि की उपलब्धता, नीति निर्माण और व्यापार करने में

आसानी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात की गई। निवेशकों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें प्रस्तावित नीति में स्थान दिया जाएगा।